आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव आँचल

वर्ष 47 अंक 50 (प्रति रविवार) इंदौर, 01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

मोदी कैबिनेट ने इंदौर-मुंबई नई रेल लाइन प्रोडेक्ट को दी मंजूरी

परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये है और यह 2028-29 तक पूरी हो जाएगी

निर्माण के दौरान परियोजना लगभग 102 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी

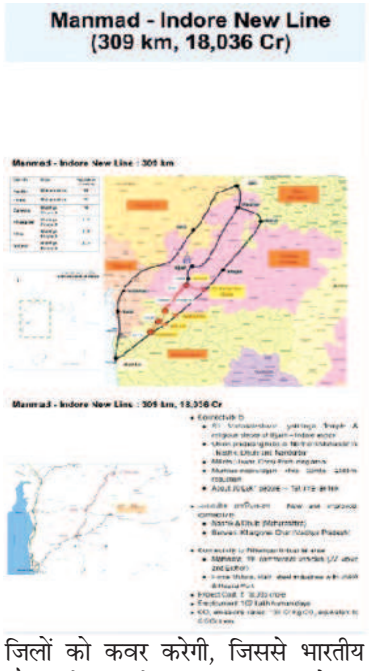

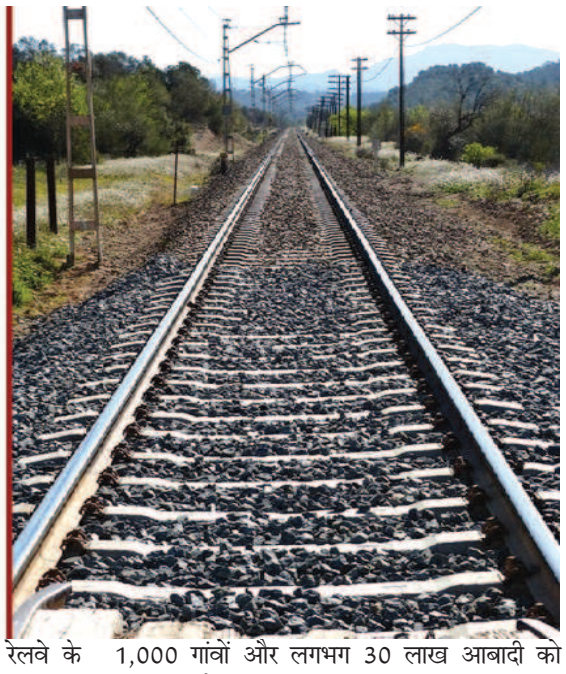

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय के तहत 18,036 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन्दौर और मनमाड के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधा सम्पर्क प्रदान करेगी और गतिशीलता में सुधार करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नए भारत की कल्पना के अनुरूप है, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध सम्पर्क प्रदान करेगा। यह परियोजना 2 राज्यों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर सम्पर्क मिलेगा। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को सम्पर्क मिलेगा।

मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी 7 सौगात -मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,966 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पहला अहम निर्णय है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमने सफलता हासिल की है, कुल 20,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, डिजिटल कृषि मिशन स्थापित किया जाएगा। दूसरा अहम निर्णय है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके तहत 3979 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसल उगाने करने के लिए तैयार किया जाएगा।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं?

नई दिल्ली। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है, क्योंकि वह आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता।

दोषी का घर भी नहीं गिराया जा सकता-जस्टिस बीआर गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है? अगर वह दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद

भी हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है, तो यह तरीका नहीं है।

17 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। हम पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई। दरअसल, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की।

केंद्र सरकार का तर्क- कानून का उल्लंघन करने पर ही होती है कार्रवाई-सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। इसके जवाब में पीठ ने कहा, लेकिन शिकायतों को देखते हुए, हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है।

कंगना ने फिर लिया पंगा, जया को बताया पैनिक अटैक वाली महिला

नई दिल्ली,(एजेंसी)। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन का गुस्सैल मिजाज से सभी वाकिफ हैं जया छोटी सी बात पर भड़क जाती हैं और अपना गुस्सा जाहिर करती नजर आती हैं। पिछले दिनों वह पार्लियामेंट में उनके पति अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित किए जाने पर नाराज हो गई थी। अब हाल ही में बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने जया बच्चन के इस रवैये पर टिप्पणी की है, जिसको लेकर वह चर्चाओं में हैं। जया बच्चन के उस रिएक्ट पर हाल ही में कंगना ने कहा कि वह पैनिक अटैक वाली महिला हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग बनाया है और दोनों के बीच खूबसूरत अंतर है। आजकल फेमिनिज्म के नाम पर कुछ महिलाएं खराब डायरेक्शन में जाने से नहीं चूक रहीं हैं। हमारी सोसाइटी उस डायरेक्शन में जा रही है, जहां उन्होंने एरोगेंस को छोड़ा नहीं है। चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि लोगों को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी कहीं छूट गई है, उनको पैनिक अटैक आ जाता है। लोग इतना डरे हुए हैं, जबकि ये कितनी बुरी बात है।

संपादकीय

शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। यह घटना 26 अगस्त 2023 को घटित हुई, उसके बाद से ही राज्य में उथल-पुथल मची हुई है। इस मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी आक्रामक मुद्रा में है। भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आमने-सामने आकर खड़ी हो गई हैं। महाविकास आघाड़ी ने इस घटना को लेकर राज्यभर में आंदोलन शुरू कर दिया है। 1 सितंबर 2024 को महा विकास अघाड़ी ने मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एक विशाल रैली निकाली, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को शिवाजी महाराज के अपमान और भ्रष्टाचार से जोड़कर विपक्ष सरकार और प्रशासन पर दबाव बना रहा है। प्रतिमा निर्माण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितताएं बरती गईं, जिस कारण यह दुर्घटना हुई। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिसके कारण जवाब में बीजेपी को भी मैदान में उतरना पड़ा है। मुंबई में भाजपा ने दादर ईस्ट से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। भाजपा का आरोप है, कि महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा इस मामले में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार माफी मांग चुके हैं। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह मामला महाराष्ट्र के चुनाव में एक महत्वपूर्ण असर डालने वाला होगा। विधानसभा चुनावों के निकट आते ही इस घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। एनडीए के घटक दल शिवसेना (एकनाथ शिंदे) राकापा के (अजीत पवार) और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का विभिन्न समुदायों के बीच गहरी आस्था और सम्मान है। चुनाव के ठीक पहले उनकी मूर्ति का गिर जाना अशुभ माना जा रहा है। मूर्ति बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है। उसको लेकर विपक्ष शिवाजी महाराज के मान अपमान से जोड़ते हुए सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे है। सत्ता पक्ष के लोग सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए भगवान और देवता को भी नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के आरोप लगाकर विपक्ष सरकार और भाजपा पर हमलावर है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यह आरोप भाजपा को भारी पडते हुए दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला आने वाले दिनों में और भी गहराएगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओर एनडीए के सहयोगी दलों को भारी नुकसान होने की आशंका वक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर शिवाजी महाराज को देवता बताते हुए सार्वजनिक रूप से मस्तक झुका कर माफी मांगी है। आमतौर पर प्रधानमंत्री जल्द माफी नहीं मांगते हैं। उन्होंने अभी तक केवल एक बार किसानों से माफी मांगी है। उसके बाद शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी। लगता था, यह मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यह मामला ठंडा पड़ने के स्थान पर दिनों-दिन और भी गर्म होता जा रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है। जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में शिवाजी महाराज को लेकर विपक्ष के पास सत्ता पक्ष पर भावात्मक रूप से जोरदार हमला करने का मौका मिल गया है। चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के हाथ में एक तुरुप का पत्ता लग गया है। इसका लाभ विपक्ष को महाराष्ट्र की राजनीति में होता हुआ दिख रहा है। इस घटना से इतना तो तय हो गया है, यह समय भाजपा के लिए अच्छा नहीं है।

सर्वसुलभ इंसाफ की उम्मीद को पंख लगे

ललित गर्ग

यह सुखद, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक अवसर ही है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 75 साल का गरिमामय सफर पूरा कर लिया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को यादगार बनाने के लिये बाकायदा डाक टिकट व सिक्के भी हाल ही में जारी किये गए और विभिन्न आयोजनों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के विषय पर गंभीर मंथन भी हुआ, ऐसे ही आयोजनों में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) डी.वाई. चंद्रचूड ने इस बात पर बल दिया कि समय पर न्याय मिलने से ही न्याय का वास्तविक लक्ष्य पूरा होता है। 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है' वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।'

सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती के अवसर पर सभी ने शीघ्र न्याय की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति से तौबा करने का वक्त आ गया है? न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए। यही वजह है कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कुछ कहा, उसे देश की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए अलार्म बेल माना जा सकता है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि जब तक न्यायपालिका देश के आम लोगों को सहजता से इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता मुहैया नहीं कराती, तब तक उसका काम पूरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वीकारा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिये बड़ी चुनौती है।

अदालतों से न्याय पाने की प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है और इसमें बेहिसाब वक्त लगता है। इन दोनों ही का नतीजा इसी रूप में सामने आता है कि इंसाफ की आस लेकर अदालत पहुंचा व्यक्ति फैसला आने तक टूट चुका होता है। इसीलिये राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि किसी गंभीर अपराध से जुड़े मामले का फैसला आने में 32 साल लग जाए तो लोगों को ऐसा लगना अस्वाभाविक नहीं कि शायद अदालतें ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। राष्ट्रपति ने किसी खास मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा अजमेर में पॉक्सो अदालत द्वारा इसी 20 अगस्त को सुनाए गए फैसले की तरफ था। एक चर्चित सेक्स स्कैंडल से जुड़े इस मामले में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने में 32 साल लग गए। यह अपनी तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। बेहद गंभीर और वीभत्स अपराध के सैकड़ों ऐसे मामले हैं, जो अदालतों में बरसों से लंबित पड़े हैं। लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश-निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हों? प्रश्न यह भी है उन्हें समय पर त्वरित न्याय कब मिल सकेगा? दुर्भाग्य से ये प्रश्न दशकों से अनुत्तरित है।

इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके। निस्संदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। पूरे देश में अपराधियों को शीघ्र व सख्त दंड देने की मांग की जा रही है। यदि पुलिस व जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पहुंचें तो गंभीर मामलों में आरोप जल्दी सिद्ध हो सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मज़बूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, ग़रीबों के अधिकार एवं सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ़ कमज़ोर समूहों का योग्य संरक्षक और करोड़ों नागरिकों के लिए आखरी उम्मीद वाला संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले 75 वर्षों में ज्यादातर समय भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा और क़ानून के शासन को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था के सामने अनेक जटिल स्थितियां भी हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बढ़ते केसों की संख्या, जवाबदेही, भ्रष्टाचार एवं विलम्बित न्याय आदि। न्याय को लेकर अदालतों तक आम नागरिकों की पहुंच एवं खर्च के मुद्दों और इसी तरह की दूसरी चीज़ों के मामले में सुधार के बारे में न्यायपालिका की अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हमारे कानूनों की भावना है- नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले है।

निश्चित ही डी.वाई. चंद्रचूड न्याय-प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं तो उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दिये हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देती रही है। न्याय के इंतजार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80 हजार है। उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या 62 लाख के करीब है और निचली अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़। इसका अर्थ है कि लगभग पांच करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। देश में तीनों स्तरों पर लंबित मामले न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। आजादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके देश की इस त्रासद न्याय व्यवस्था के बाबत देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित ही भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है।

निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी ही चाहिए। जैसाकि अमेरिका में किसी भी मामले के लिये तीन वर्ष की अवधि निश्चित है। लेकिन भारत में मामले 20-30 साल चलना साधारण बात है। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशों की तरह भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका है। तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके इसके लिये हाल ही में लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। नये तीन कानूनों के बाद मुकदमों की सुनवाई द्रुत गति से होगी, लेकिन देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं?

सिटी बस में सीईओ सिंह ने किया सफर, यात्रियों से की चर्चा

ड्राइवर-कंडक्टर को दिए ट्रैफिक नियम पालन के निर्देश

इंदौर। एआईसीटीएसएल की कमान संभालते ही नए सीईओ दिव्यांक सिंह यात्रियों के सुखद सफर के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सीईओ दिव्यांक सिंह ने स्वयं सिटी बस में सफर का आनंद लिया। साथ ही यात्रियों से भी सिटी बस के सफर के बारे में चर्चा की। सीईओ सिंह ने यात्रियों से यह भी जानकारी ली कि ड्राइवर और कंडक्टर का उनके प्रति व्यवहार कैसा है। सिटी बस में सफर कर रहे लोगों से सीईओ ने गाड़ियों के मेंटेनेंस और आरामदायक सफर आदि के बारे में सुझाव भी लिए। जानकारी अनुसार एआईसीटीएसएल की स्थापना के बाद कई अधिकारियों ने सीईओ का कार्य संभाला, लेकिन वर्तमान सीईओ दिव्यांक सिंह पहले से सीईओ हैं, जिन्होंने स्वयं बस में सफर कर यात्रियों से चर्चा की और सिटी बस के सफर के बारे में जानकारी ली।

सीईओ ने सिटी बस ओके सुचारू संचालन आदि के लिए सिटी बस डिपो, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस डिपो का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही वहां उपस्थित कर्मचारियों से भी चर्चा की। इसके बाद सीईओ सिंह सिटी बस में सफर करने के लिए निकल गए। उन्होंने बस में सफर किया और उपस्थित यात्रियों से सिटी बस के सफर के बारे में चर्चा की। साथ ही बस ड्राइवर और कंडक्टर के व्यवहार के बारे में भी लोगों से जानकारी हासिल की।

यातायात नियमों के अनुरूप ही शहर में चलाएं वाहन

सीईओ दिव्यांक सिंह ने सिटी बस चलाने वाले ड्राइवर से भी चर्चा की। साथ ही ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स के अनुसार ही शहर में बसें चलाने के निर्देश दिए। ड्राइवर-कंडक्टरों को भी सिंह ने निर्देश दिए कि बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ बेहतर और अच्छा व्यवहार किया जाए। नियम अनुसार निर्धारित किराया ही लिया जाए। अधिक किराया लेने या खराब व्यवहार की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर को यह भी निर्देश दिया कि निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए शहर में बसें चलाई जाएं।

नायता मुंडला बस स्टैंड 8 सितंबर से शुरू होगा

600 बसों के संचालन का इंतजाम, एआईसीटीएसएल की बसें भी यहीं से चलेंगी

***इन्दौर।** नायता मुंडला में बनाए गए आईएसबीटी से एक सितंबर से बसों का संचालन शुरू होना था। लेकिन, एप्रोच रोड अधूरी होने से अब 8 सितंबर से बस स्टैंड को शुरू किया जाएगा। यहां से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली बसों को चलाया जाएगा।*

शहर के अंदर से महाराष्ट्र के लिए चलने वाली लंबी दूरी की सभी बसों को नायता मुंडला बस स्टैंड से ही चलाया जाएगा। इसमें एआईसीटीएसएल की महाराष्ट्र जाने वाली करीब 22 बसों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। ये बसें अभी गीता भवन चौराहा के पास एआईसीटीएसएल के बस स्टैंड से संचालित होती हैं। शहर में अन्य स्थानों से संचालित होने वाली बसों को भी यहां पर स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि शहर के अंदर से बसों का दबाव कम किया जा सके। नायता मुंडला बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं। यहां से प्रतिदिन 600 बसें संचालित हो सकेंगी। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग से पार्किंग बनाई गई है। तीन सौ दोपहिया और डेढ़ सौ चार पहिया वाहन यहां पार्क हो सकेंगे। परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

बस मेंटेनेंस के लिए नए डिपो बनेंगे

शहर में वर्तमान में सिटी बसों के मेंटनेंस के लिए 9 डिपो हैं। जबकि, बसों की संख्या के लिहाज से डिपो की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए नई जगह तलाश रहे हैं। इसके साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए विज्ञापन प्रदर्शन के लिए नई जगह तैयार करने के लिए कहा है। यात्रियों ने भी यात्रा के दौरान आने वाली परेशानी के बारे में बताया है, जिसे दूर किया जाएगा।

अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) में सीईओ की जिम्मेदारी मिलने के बाद दिव्यांक सिंह ने सिटी बस, आई-बस, बीआरटीएस आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों से चर्चा की। संबंधित कर्मचारी व सुपरवाइजर भी इस दौरान मौजूद थे। सीईओ ने बताया कि सिटी और आई बस में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखकर निरीक्षण किया। इसमें सामने आया कि बसों की बेहतर सफाई नहीं होती है। साथ ही समय पर संचालन भी नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस की व्यवस्था हुई लागू, लगाई गई 6 थंब मशीन

इन्दौर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार 2 सितम्बर 2024 से कलेक्टर कार्यालय और इससे लगे सैटेलाइट भवन में बायोमेट्रिक मशीनों द्वारा हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी। यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है। अटेंडेंस दर्ज करने के लिए कुल 6 बायोमेट्रिक थंब मशीनें लगाई गई है। सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित समय पर कार्यालय उपस्थित होना होगा और अपने अंगूठे की निशानी दर्ज करानी होगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी सुश्री मोनिका कटारे ने बताया है कि कलेक्टर कार्यालय सहित सैटेलाइट भवन में कुल 6 बायोमेट्रिक मशीनों की स्थापना कर दी गई है। सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ते वक्त भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी आधार पर शासकीय सेवकों का वेतन आहरित किया जायेगा। ऐसी ही व्यवस्था अन्य विभागों में भी लागू की जायेगी।

संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने एमवाय अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

एमवाय सहित अन्य शासकीय अस्पतालों के सीसीटीवी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़े जाएं, सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की समिति की बैठक में दिये निर्देश

इन्दौर। संभागायुक्त दीपक सिंह,पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण ने एमवाय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, एमरजेंसी वार्ड, उपचार कक्ष, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, डॉक्टर्स एवं स्टूडेंट ड्यूटी रूम सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण के पश्चात इंदौर स्थित विभिन्न शासकीय अस्पतालों में सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की समिति की बैठक ली।

बैठक में संभागायुक्त सिंह ने निर्देश दिये कि एमवाय सहित अन्य अस्पतालों में लगे सीसीटीवी कंट्रोल रूम को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाये जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति की मॉनिटरिंग और बेहतर तरीके से हो सकें तथा आकस्मिक स्थिति होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सकें। उन्होंने ने सीसीटीवी कैमरों का आडिट कराये जाने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने एमवाय, एमटीएच, आई हॉस्पिटल, बाणगंगा स्थित मानसिक चिकित्सालय सहित अन्य शासकीय चिकित्सालयों में सुरक्षा प्रबंधों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने इन अस्पतालों में चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टॉफ आदि की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। संभागायुक्त सिंह ने निर्देश दिये कि सीसीटीवी सर्विलेंस को सशक्त करते हुए माइक एड्रेस सिस्टम को बेहतर किया जाये।

एमवाय, एमटीएच सहित अन्य अस्पताल परिसरों में बाउंड्रीवाल निर्माण एवं पुराने जर्जर भवनों को हटाने सहित अन्य निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि हॉस्पिटल केम्पस में रोशनी हेतु स्ट्रीट लाइट के बेहतर प्रबंध किये जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि समिति में प्राप्त सुझाव को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। अस्पताल परिसर में तैनात निजी सुरक्षा बलों को शोल्डर कैमरे उपलब्ध कराये जाये। ब्रेथ एनालइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंधों की मॉकड्रील की जाये। कलेक्टर आशीष सिंह ने अस्पताल परिसरों में बॉउंड्रीवाल निर्माण एवं जीर्णशीर्ण भवनों को तत्काल हटाने संबंधी आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों के डॉक्टर्स ने बेहतर प्रबंधों, सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में एडिशनल सीपी अमित सिंह, डीसीपी हंसराज सिंह, डीन एमजीएम कॉलेज डॉ संजय दीक्षित, डॉ सुमीत शुक्ला सहित पीडब्लूडी, पीआईयू सहित विभिन्न अस्पतालों के अधीक्षक एवं चिकित्सकगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बाउंड्रीवाल निर्माण एवं बेरिकेटिंग हेतु स्थल का किया निरीक्षण-कलेक्टर आशीष सिंह ने एमवाय अस्पताल परिसर में आम आवाजाही रोकने हेतु बेरिकेटिंग करने एवं जीर्णशीर्ण भवनों को हटाने के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने एमवाय अस्पताल परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण एवं बेरिकेटिंग किये जाने हेतु स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एमवाय अस्पताल परिसर में जीर्णशीर्ण भवनों की स्थिति का भी अवलोकन किया तथा उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में आम आवाजाही के मार्ग पर बेरिकेटिंग की जाये तथा जीर्णशीर्ण भवनों को हटाने की कार्यवाही की जाये। इस दौरान डॉ. सुमित शुक्ला, डॉ. अशोक यादव सहित पीडब्लूडी, पीआईयू के अधिकारी उपस्थित थे।

संगठन पर्व हमारे लिए पार्टी का सबसे बड़ा त्योहार, इसे ऐतिहासिक बनाएं : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी कार्यालय में भोपाल जिले के मोर्चों एवं प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक एवं मिसरोद मंडल के बूथ क्रमांक 302 की संगठन पर्व बूथ कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का संगठन पर्व हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है।

हमें प्राणप्रण से जुटकर सदस्यता के लिए पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करना है। सदस्यता अभियान सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि कमजोरी को मजबूती में बदलने का अवसर है। कांगेस ने आजादी के बाद से ही देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीबों का जीवन संवार रहे हैं, उन्हें मजबूती देने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सदस्य बनाएं। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस ने झूठ और छल-कपट की राजनीति है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब के इलाज चिंता की। ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम समाज की महिलाओं को नरक से झुटकारा दिलाने का कार्य किया।

गरीबों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और मकान दिया है। हमें अल्पसख्यकों के पास जाकर उन्हे पार्टी से जोड़ना है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता को झोपड़ी में रहने वाले को भी सदस्य बनाना है। पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था हमारा परंपरागत विरोधी है, उन्हें भी मतदाता बनाना है, जो मतदाता बन गये हैं, उन्हें सदस्य बनना है। उन्होंने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, उनमें मजबूती प्रदान करने के लिए है। देश में आज भी कई ताकतें विद्वेष फैला रही हैं। इन ताकतों पर प्रहार करने के लिए भाजपा का शक्तिशाली होना जरूरी है। इसलिए सदस्यता अभियान में पार्टी का विस्तार कर पार्टी की ताकत बढ़ाएं। शर्मा ने भोपाल में गोविंदपुरा विधानसभा के मिसरोद मंडल के बूथ क्रमांक 302 की संगठन पर्व कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के आजाद होने के तुरंत बाद से ही देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का कार्य किया है। स्व. जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य को अलग स्वायत्तता प्रदान करने का प्रावधान संविधान में करा दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग, प्रधानमंत्री अलग हो गया। तब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की और एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेगा का नारा देते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए आंदोलन किया और बलिदान दिया। जनसंघ ही आगे चलकर वर्ष 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। आप सभी गर्व करें कि उस पार्टी के सदस्य हैं, जिनके नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया। आप लोगों की मेहनत से स्पष्ट बहुमत की केंद्र में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। अब कश्मीर के लालचौक पर 24 घंटे शान से तिरंगा लहरा रहा है।

भोपाल के कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाकर लक्ष्य हासिल करने में जुए जाएं

शर्मा ने कहा कि संगठन पर्व हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। समय कम है हमें मेहनत ज्यादा करनी है। मोर्चा प्रकोष्ठ हमारी ताकत है। हमें हर बूथ पर 200 से अधिक नए सदस्य जोड़ना है और इस काम में हर मोर्चे की भूमिका होगी। मोर्चा और प्रकोष्ठ योजनाएं बनाकर कार्य प्रारंभ करें सफलता अवश्य मिलेगी। भोपाल में कुछ विधानसभा सीटें ऐसे लोगों के हाथ में है जो दिन भर देशद्रोही ताकत के साथ खड़ी रहती है। हमें इन विधानसभाओं के बूथों पर अधिक फोकस करना है। उन्होंने कहा कि हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बनाने का माध्यम हैं। सदस्यता अभियान में भोपाल के कार्यकर्ता अपनी-अपनी भूमिका निभाकर लक्ष्य हासिल करने में जुट जाएं।

प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने सभी मतदाताओं को सदस्य बनाएं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों का जीवन संवारने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूत संगठन के साथ प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक विजय दिलाई है। प्रधानमंत्री के हाथ को और मजबूती देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पार्टी का सदस्य बनाकर मोदी को और ताकतवर बनाने का कार्य करें।

मप्र कैसे बनेगा होनहार: महानगरों में शिक्षकों की भरमार, ग्रामीण स्कूलों में टोटा

>> प्रदेश में शिक्षकों के 70 हजार पद खाली...प्राथमिक शिक्षा के स्तर में लगातार हो रही गिरावट >> 1275 स्कूल शिक्षक विहीन, 22,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

भोपाल। मप्र में स्कूली शिक्षा को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने निजी स्कूलों की तरह सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूलों को खोला है। वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि 46 जिलों की 1275 स्कूलों में शिक्षक शून्य हैं, जबकि करीब 22,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और लगभग 3,500 स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। उधर, महानगरों में शिक्षकों की भरमार है, वहीं ग्रामीण स्कूलों में टोटा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों के करीब 79 हजार पद खाली हैं। हालांकि इस साल नौ हजार पदों पर भर्ती होने के बाद भी करीब 70 हजार पद खाली रह जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मप्र का भविष्य होनहार कैसे बनेगा?

मप्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और असमानता एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में शिक्षकों की भरमार है, जबकि अन्य जिलों के स्कूल खाली पड़े हैं। इस असमानता के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में पदस्थ करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के कई बड़े शहरों में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। इसमें, इंदौर में 1,337, ग्वालियर में 1,153, भोपाल में 1,115, और जबलपुर में 887 अतिशेष शिक्षक पदस्थ हैं। वहीं, बालाघाट, सतना, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, भिंड, मुरैना, और देवास जैसे जिलों में शिक्षकों की संख्या अत्यधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली पड़े हैं। प्रदेश के करीब 22,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और लगभग 3,500 स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन शिक्षक तैनात हैं।

ऐसी है स्कूलों की स्थिति-प्रदेश में 1 लाख 22 हजार सरकारी स्कूल हैं, इनमें एक करोड़ 10 लाख विद्यार्थी हैं। इनके लिए तीन लाख 16 सौ 20 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में दो लाख 26 हजार 234 शिक्षक कार्यरत हैं। इस तरह शिक्षकों के 79 हजार 496 पद खाली हैं। ये आंकड़ें बताते हैं कि स्कूली शिक्षा के हाल बेहाल हैं। राजधानी भोपाल के बड़वाई सरकारी स्कूल को ही देख लीजिए। यहां पहली से 5वीं तक 47 बच्चे हैं लेकिन शिक्षक एक ही हैं। एक बोर्ड में ही सभी विषयों की पढ़ाई होती है। वहीं डिंडौरी का अनोखा स्कूल भी हमने आपको दिखाया है, जहां प्रभारी प्राचार्य ही शिक्षक, बाबू और चपरासी भी है।

कक्षाओं में सब्जेक्ट टीचरों का भी टोटा-प्रदेश में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 9 हजार से ज्यादा है। पिछले सत्र में इन कक्षाओं में 10 लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत थे। नए सत्र में यह संख्या कुछ और बढ़ सकती है। वहीं शिक्षकों की बात करें तो हास्यास्पद होगी। 9 हजार में से 60 फीसदी भी ऐसे नहीं है जहां स्थाई प्राचार्य पदस्थ हो। यहां भी काम शिक्षकों को प्रभार देकर चलाया जा रहा है। कक्षाओं में विषयवार शिक्षक भी नहीं हैं। कहीं गणित के शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कहीं कला संकाय के शिक्षकों के हवाले कॉमर्स और विज्ञान के छात्र हैं। प्रदेश में 30 फीसदी भी स्कूल ऐसे नहीं है जहां छात्रों को पढ़ाने वाले विषयवार शिक्षकों की कमी न हो।

विभाग और संचालनालय ने मूंद ली आंखें-शिक्षकों की कमी के कारण प्रदेश में स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में स्कूलों में रिजल्ट खराब रहने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए थे। इसमें भी पढ़ाई में सुधार नहीं अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने के निर्देशित थे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी क्लब के कार्य प्रशंसनीय-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कान्फ्रेंस से किया संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रोटरी क्लब उज्जैन द्वारा संचालित इंटरसिटी साक्षरता कार्यक्रम के प्रतिनिधियों को आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा जुड़कर रोटरी क्लब के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की और उनके प्रकल्पों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कई जन्मों के पुण्य के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इसके साथ ही सेवा का अवसर भी मिलता है। अपने सद्कर्मों से मानव बना जा सकता है। अच्छे कार्य मनुष्य को देव बना देते हैं। देव या देवता वही होता है जो देने का भाव रखे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोटरी क्लब के सदस्यों को उज्जैन में रक्तदान जैसे पुण्य कार्य के लिए अधोसंरचना तैयार करने और रतलाम में रोगियों के लिए डायलेसिस की सुविधा प्रारंभ करने की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन का एक नाम अवंतिका भी है, जिसका अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। उज्जैन का प्रत्येक युग में महत्व रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोटरी क्लब के कार्यक्रम में उज्जैन आए अन्य स्थानों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में साइंस सिटी, प्लेनोटोरियम, वैदिक घड़ी जैसे स्थान भी देखकर जाएं। उज्जैन में साइंस सिटी बनाने की पहल इसे धार्मिक नगरी के साथ ही विज्ञान सिटी बनाने में सहयोगी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन का गौरवशाली अतीत है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां आकर शिक्षा ग्रहण की। रोटरी क्लब द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा कार्य अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोटरी क्लब के कार्यक्रमों और प्रकल्पों की सफलता की कामना की। कार्यक्रम में श्री अविनाश गुप्ता, समन्वयक के साथ ही अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

आधुनिक तकनीक से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले म.प्र. ने किया शुरू : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने नागरिकों को उत्तम सेवाएँ उपलब्ध कराने राजस्व टीम को दी बधाई

राजस्व महाभियान के 2 चरणों में 80 लाख प्रकरणों का निराकरण

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिये प्रांतव्यापी चलाए गये राजस्व महाअभियान के 2 चरण कारगर सिद्ध हुए हैं। जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य के साथ चलाए गए राजस्व महाअभियानों में 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने शुरू किया है।

डॉ. यादव ने नागरिकों को उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम को बधाई दी। उन्होंने उन सभी नागरिकों को भी बधाई दी है, जिनके लंबित मामलों का निराकरण हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेशसरकार जनसेवा और आम जन की समस्याओं के निराकरण के

लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 49 लाख 15 हजार 311 मामले निराकृत हुए। साथ ही 88 लाख से अधिक ई-केववायसी पूरी की जा चुकी हैं। इससे पहले राजस्व महाअभियान 1.0 में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व-महाअभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 तक जारी रहा। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ। पहले चरण के राजस्व महाभियान की सफलता एवं जनता की सराहना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दूसरे चरण का राजस्व महाभियान शुरू करने के निर्देश दिये। यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चला। इसमें राजस्व न्यायालयों में समय-सीमा पर लम्बित नामांतरण, बँटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण किया गया। साथ ही नक्शे पर तरमीम उठाना और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग का कार्य किया गया। महाअभियान में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण का कार्य, फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन और पीएम किसान में सभी हितग्राहियों को शामिल करने का कार्य भी किया गया। राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की सतत मॉनिटरिंग राजस्व महाभियान डैशबोर्ड के माध्यम से की गई।

36 जिलों में शत-प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरण किये निराकृत- आलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाडी, नीमच, पन्ना, पांढुर्णा, बड़वानी, बालाघाट बुरहानपुर, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, मंडला, मऊगंज, मन्दसौर, मुरैना, मैहर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, शहडोल, श्योपुर, सतना जिलों में लंबित नामांतरण प्रकरणों का 100प्र. निराकरण किया गया है। शेष जिलों में 99प्र. से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार कुल 99.98प्र. लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण राजस्व महाभियान 2.0 में किया गया है।

बंटवारा प्रकरणों का सभी जिलों में शत-प्रतिशत निराकरण-बंटवारा लंबित बंटवारा प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण समस्त जिलों द्वारा किया गया है। अभिलेख दुरुस्ती लंबित अभिलेख दुरुस्ती प्रकरणों का भी शत-प्रतिशत निराकरण समस्त जिलों द्वारा किया गया है। इसी प्रकार बुरहानपुर, खंडवा, पांढुर्णा, सिवनी, बैतूल, झाबुआ जिलों में लंबित नक्शा तरमीम के 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों निराकरण किया गया है।

मध्यप्रदेश में पर्यटन क्रांति लाएगा आईएटीओ–उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तीन क्रांतियां जरूरी है। पहली हरित क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी पर्यटन क्रांति है। देश और मध्यप्रदेश में पर्यटन क्रांति को लाने में आईएटीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल आईएटीओ के 39वें अधिवेशन के समापन समारोह को होटल ताज में संबोधित कर रहें थे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। आईएटीओ के सदस्य इस अधिवेशन के माध्यम से मध्यप्रदेश के पर्यटन को करीब से जानेंगे और पर्यटकों को इसकी जानकारी देंगे। इससे निकट भविष्य में मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आईएटीओ के सदस्य टूर और ट्रैवल ऑपरेटर से विदेशी पर्यटकों के बीच मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार करने और मध्यप्रदेश आने के लिए प्रेरित करने का आग्रह भी किया।

संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्य बनेगा। मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के आईएटीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री श्री लोधी ने आईएटीओ सदस्यों को मध्यप्रदेश की पर्यटन संबंधी विशेषताओं और पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के शासन के प्रयासों की जानकारी दी।मंत्री श्री लोधी ने कहा कि कन्वेंशन के बाद सभी आईएटीओ सदस्यों को स्पेशल टूर के माध्यम से मध्यप्रदेश का भ्रमण कराया जायेगा। सभी सदस्य मध्यप्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को करीब से जान पायेंगे। मंत्री श्री लोधी ने सभी आईएटीओ सदस्यों से अधिक से अधिक संख्या में मध्यप्रदेश में आमंत्रित करने का आग्रह किया।

आईएटीओ अध्यक्ष राजीव मेहरा ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने आईएटीओ सदस्यों की तरफ से मध्यप्रदेश में अधिक संख्या में पर्यटकों को लाने का भरोसा भी दिया। आईएटीओ अध्यक्ष राजीव मेहरा ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल और राज्यमंत्री श्री लोधी को सम्मान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। आईएटीओ के मध्यप्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अमानक दवाई मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई : संगीता शर्मा

कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच के लिए मांगा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा

भोपाल। सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ताहीन दवाओं की सप्लाई करने के मामले में कांग्रेस ने स्वाथ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले दवाई सप्लायरों और दोषी अफसरों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने और उक्त मामले की जांच राज्य के बाहर की किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टार्लेस की बात तो करते हैं पर यहां तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। सुश्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता इनके नजर में कोई मायने नहीं रखती। 15 दिन में तीसरी बार अमानक दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगना यह बताता है कि भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की नस - नस में समय हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री शर्मा ने कहा कि जनता के लिए चलने वाली योजनाओं में भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करने वाले अब तो प्रदेश की जनता की सेहत से भी खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे।

सुश्री शर्मा ने कहा कि हाल तो यह है कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाला ओआरएस पाउडर भी ख़राब क्वालिटी का पाया गया। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी 3 की टैबलेट अमानक पाई गई है। सुश्री शर्मा ने कहा कि बैतूल, देवास और धार में दवाओं की लैब टेस्टिंग कराने पर सभी दवाइयां फेल पाई गई है। लगभग पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में वितरित की गई दवाएं अमानक स्तर की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर अमानक दवाई की सप्लाई बिना सरकार में शामिल लोगों की सहमति से संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री डा मोहन यादव को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत स्वास्थ मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा की इसके अलावा इस बड़े घोटाले की जांच सीबीआई या किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से करानी चाहिए ताकि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो सके।

अब तक क्या कर रही थी सरकार

कांग्रेस प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक का निर्देश भले दे दिया गया है पर इतने बड़े पैमाने पर अमानक दवाई वितरण में सरकारी तंत्र क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को कई जीवन रक्षक इंजेक्शन समेत कुल 9 दवाओं के लॉट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सुश्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन ने सभी जिलों के डीन, सीएमएचओ, और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में संगठित भ्रष्टाचार का इसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करे क्योंकि कांग्रेस प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं करने देगी।

इन अभिनेत्रियों ने ट्रोलिंग के कारण डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम हैंडल

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों को कई बार अपने लुक को लेकर तो कई बार अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ अभिनेत्रीयों ने ट्रोलिंग से परेशान होकर अपने सोशल मीडिया हैंडल को डिलीट करने का फैसला तक लिया था। चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किन अभिनेत्रीयों का नाम शामिल हैं।

आयशा टाकिया

आयशा टाकिया ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने बीच में कुछ दिनों तक अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का फैसला किया था। हालांकि अब वह इस्टाग्राम पर वापसी कर चुकी हैं।

दिशा पाटनी

बॉलीवुड की ग्लैमरस अभिनेत्री दिशा पाटनी को उनकी तस्वीरों और वीडियो के लिए कई बार ट्रोल किया गया है। ऐसे में एक दफा परेशान होकर दिशा पाटनी ने अपने इंस्ट्राग्राम को डिलीट करने का फैसला किया था। ऐसे में दिशा पाटनी ने बुरे कमेंट्स से तंग आकर कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम से दूरी बनाई थी।

सोनाक्षी सिन्हा

बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं। लॉकडाउन के दौरान सोनाक्षी को उनकी शरीर के आकार के कारण इतना अधिक ट्रोल किया गया कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर करने का फैसला किया था।

अनुष्का शर्मा की ड्रेस देख भड़के लोग

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं और उनकी कोई भी तस्वीर या वीडियो सामने आते ही तेजी से वायरल हो जाती है। इस वक्त अनुष्का शर्मा अपने एक लुक को लेकर ट्रोल हो रही हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ शर्ट पहनी हुई है। इस लुक में अनुष्का शर्मा को लेकर फैंस का कहना है कि वो अजीब लग रही हैं। इस तस्वीर को एक इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया गया है और लिखा है कि इस शर्ट की कीमत 8200 रुपए है। इसके बाद वो ट्रोल हो रही हैं। बता दें कि इस तस्वीर में अनुष्का शर्मा ने पैंट नहीं पहना हुआ है। उनके साथ विराट कोहली भी खड़े होकर पोज दे रहे हैं। जैसे ही तस्वीर सामने आई वो वायरल हो गई। लोग कर रहे हैं ट्रोल इस तस्वीर के सामने आते ही लोगों ने ट्रोल करना शुरु किया है।

कोलकाता की घटना से आहत होने के बाद श्रेया घोषाल ने रद्द किया लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम में गायिका श्रेया घोषाल भी शामिल हो गई हैं। मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने कोलकाता में सितंबर में होने वाले अपने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को रद्द करने का ऐलान किया है। श्रेया घोषाल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा, 14 सितंबर को कोलकाता में होने वाले लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को अक्टूबर के लिए री-शेड्यूल किया गया है। उन्होंने कहा, मैं हाल ही में कोलकाता में हुई जघन्य घटना से काफी आहत हूं। एक महिला होने के नाते, उसके साथ हुई क्रूरता के बारे में सोचना भी अकल्पनीय है और इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कॉन्सर्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन, उनके लिए इस मुद्दे पर एकजुट होकर एक स्टैंड लेना और प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी था। साथ ही उन्होंने बयान में कहा, मैं इस दुनिया और हमारे देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं।

बिना किसी झंझट के तैयार हो जाएगी एगलेस ब्राउनी

ब**च्चों** को ही नहीं बड़ों को भी ब्राउनी बेहद पसंद होती है। लेकिन बाहर से मंगाने पर ये काफी महंगी पड़ जाती है। अगर आप ब्राउनी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। तो घर में भी ब्राउनी तैयार की जा सकती है। बस इसे बनाने की सही तरीका पता होना चाहिए। फिर देखें कैसे फटाफट चॉकलेट ब्राउनी बनकर तैयार होती है।

चॉकलेट ब्राउनी बनाने की सामग्री

मैदा आधा कप, बेकिंग पाउडर एक चुटकी, बेकिंग सोडा एक चौथाई चम्मच, कोको पाउडर एक चौथाई कप, आधा कप पिसी चीनी, एक चौथाई कप तेल, वनीला एसेंस, ड्राई फ्रूट्स टुकड़ों में कटा हुआ। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकती हैं। बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को बारीक काट लें।

चॉकलेट ब्राउनी बनाने की विधि

सबसे पहले मैदा और कोको पाउडर को छान लें। फिर किसी बाउल में दोनों को मिला लें। अब इस मिश्रण में एक चौथाई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डालकर मिला लें। अच्छी तरह चम्मच से चलाकर मिक्स कर लें। फिर इसमे आधा कप पिसी हुई चीनी को मिला लें।

सारी चीजों को चम्मच से चलाने के बाद इसमे तेल डालें। साथ में वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। थोड़ा सा दूध डालकर ब्राउनी का गाढ़ा बैटर तैयार करें। सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद इसमे कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें। अच्छी तरह से फेंटने के बाद बेक करने वाले बर्तन में डाल दें। बेकिंग ट्रे को पहले बटर की मदद से ग्रीस कर लें। अगर बटर पेपर हो तो उसे भी लगा सकती हैं। बेकिंग वाले बर्तन में एक चौथाई जगह खाली रखें। जिससे कि फूलने की जगह मिले। अगर ओवन है तो उसमे रखकर बेक करें। नहीं तो कूकर में नमक डालकर उसके ऊपर बेकिंग के बर्तन को रखें। बिना रबड़ के सीटी लगा दें और करीब चालीस मिनट तक बेक करें। बस तैयार है स्वादिष्ट ब्राउनी।

सोफी ने ब्लू गाउन में दिखाई अपनी अदाएं

सो**फी** चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कई तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उनका जबरदस्त अंदाज देखकर फैंस हैरान रह गए हैं। वे हमेशा की तरह खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं। सोफी चौधरी नीले रंग के गाउन में शानदार लग रही हैं। सोफी चौधरी चमचमाते हुए गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

शादी के बाद तलाश रही हैं चूड़ा तो ये हैं बेस्ट डिजाइन

प**हले** के समय में केवल पंजाबी दुल्हने ही चूड़ा पहना करती थीं। कहा जाता है कि चूड़ा पहनने से पति-पत्नी के बीच का संबंध मजबूत होता है। इसे भी सुहाग के निशानी के तौर पर देखा जाता है। शादी के करीब 40-45 दिन बाद महिलाएं चूड़ा उतारती है और इसे संभाल कर रखती हैं। लेकिन धीरे-धीरे यह फैशन का हिस्सा बन गया है, जिसके कारण अब नॉर्थ इंडिया की दुल्हनों ने भी यह पहनना शुरू कर दिया है। ट्रेडिशनल चूड़ा का रंग लाल होता है। यह देखने में बेहद सुंदर लगता है। लेकिन अब दुल्हनें लाल रंग और सिंपल डिजाइन के बजाय कुछ नया ट्राई कर रही हैं।

पिंक चूड़ा

ज्यादातर दुल्हनें केवल लाल या मरून रंग का ही चूड़ा पहनती हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं तो लंहगे से मैचिंग चूड़ा पहनें। इसके साथ कुंदन के कड़े खूब जंच रहे हैं।

आप भी अपनी शादी के लिए कुछ इसी तरह का चूड़ा डिजाइन सेलेक्ट कर सकती हैं। मार्केट में आपको कई रंग के चूड़े मिल जाएंगे।

कस्टमाइज्ड चूड़ा डिजाइन

जिस तरह दुल्हनें अपने लंहगे के दुपट्टे को खास बनाती हैं, उसी तरह आप चूड़ा के साथ भी क्रिएटिविटी कर सकती हैं। आजकल कस्टमाइज्ड चूड़ा डिजाइन काफी पॉपुलर हैं। इसमें आप चूड़े पर कुछ भी लिखवा सकती हैं। चाहे वह पति का नाम हो या फिर सौभाग्यवती भव जैसे मंत्र हों। यकीन मानिए यह चूड़ा देखकर हर कोई आपकी तारीफ जरूर करेगा।

राजवाड़ी चूड़ा डिजाइन

राजवाड़ी ज्वेलरी देखने में बेहद अच्छी लगती है और इसे पहन रॉयल लुक मिलता है। आपको चूड़ा में भी यह डिजाइन आसानी से मिल जाएगा। इसमें चूड़े पर अलग-अलग डिजाइन बने होते हैं। महिलाएं आजकल चूड़ा में बोरला डिजाइन भी पसंद कर रही हैं। इस तरह के चूड़े में मोती और कुंदन से कारीगरी की जाती है। आप चाहें तो केवल मोती वाली ही चूड़ा खरीद सकती हैं।

कलरफुल चूड़ा

अगर आपकी शादी होने वाली है और आप चाहती हैं कि आपका चूड़ा बेहद खूबसूरत हो तो इस बार कलरफुल चूड़ा पहनें। इसमें आप अपने पसंद अनुसार रंग चुन सकती हैं। इस चूड़े डिजाइन की खासियत यह है कि इसमें चेन भी लगाई गई है। जिसे आप कलीरे के तौर पर भी पहन सकती हैं। ऐसे में आपको इन्हें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यूनिक चूड़ा डिजाइन

आजकल मार्केट में बारीक कारीगरी वाले चूड़ा डिजाइन्स की भरमार है। यह डिजाइन देखने में बेहद सिंपल लगता है। लेकिन यह आपके लुक में एलिगेंट टच ऐड करेगा। इस तरह के डिजाइन का फोकस बीच वाले चूड़े पर रहता है। इसलिए इस पर फूल-पत्ती से लेकर डोली तक का डिजाइन बना होता है।

पैराग्लाइडिंग के लिए हैं ये बेस्ट जगहें

आ**जकल** के युवा ऐसे सफर पर जाना चाहते हैं, जहां का नजारा तो आकर्षक हो ही, साथ ही रोमांच को भी महसूस कर सकें। रोमांचक सफर के लिए लोग कई जगहों पर जाना पसंद करते हैं। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप ट्रेकिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और बंजी जम्पिंग से लेकर वाटर एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप किसी एडवेंचर एक्टिविटी को अपनाना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग एक मनोरंजक और साहसिक स्पोर्ट है, जिसमें हल्का फेब्रिक विंग जुड़ा होता है। पायलट इसी फैब्रिक विंग के नीचे बैठता है और आसान में उड़ान भरता है। पैराग्लाइडर घंटों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को इस उड़ान के जरिए पूरा कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग

हिमाचल प्रदेश में कई हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल हैं लेकिन अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो हिमाचल के बीर बिलिंग जाएं। ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है। यहां छोटे, मीडियम और लॉन्ग फ्लाइंग सेशन का लुत्फ आप उठा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए बीर टेक-ऑफ पॉइंट है और बिलिंग लैंडिंग साइट है। दोनों के बीच लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। यहां अक्टूबर से जून महीने तक पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छा समय होता है।

महाराष्ट्र का पंचगनी

पंचगनी पैराग्लाइडिंग के लिए बेस्ट जगह है। यहां की वादियों, हरियाली और सुंदर पहाड़ियों को आसमान से देखना अलग ही अनुभव महसूस कराएगा। पंचगनी में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे बेस्ट महीना नवंबर से फरवरी के बीच होता है। पंचगनी में पैराग्लाइडिंग के लिए कई टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, जैसे खिंगर, भीलर और तपोला। यहां आपको सोलो जंप की ट्रेनिंग भी दी जाती है।

मेघालय का शिलांग

भारत के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट जगहों में शिलॉन्ग है। शिलॉन्ग के शानदार नजारों को देखने के लिए पैराग्लाइडिंग मजेदार एक्टिविटी रहेगी। यहां आप 700 मीटर तक की ऊंचाई तक पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम शिलॉन्ग में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाना बेहतर समय है।

उत्तराखंड का नैनीताल

उत्तराखंड के नैनीताल में भी पैराग्लाइडिंग का अनुभव ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग करते हुए आप आसमान से सुंदर शहर को देख सकते हैं। मानसून छोड़कर आप पैराग्लाइडिंग के लिए नैनीताल कभी भी जा सकते हैं।

सिक्किम का गंगटोक

सिक्किम का गंगटोक शहर भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां का नजारा देखने लायक होता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं तो गंगटोक जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आप गंगटोक पैराग्लाइडिंग के लिए जाना बेहतर रहेगा।

देवी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा

अहिल्याबाई ने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया

इंदौर। *इंदौर के गांधी हॉल में लोक माता देवी अहिल्याबाई की 229वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या माता ने अपने कुशल प्रबंधन से 300 सालों तक की व्यवस्था की। माता अहिल्या के प्रशासन की जगह आज की प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर दिखाई देती है। उन्होंने देश भर में मालवा के मान-सम्मान को बढ़ाने का काम किया।*

सीएम यादव ने कहा कि हम राज्य स्तर पर भी मां अहिल्या समिति बनाकर प्रदेशभर में उनके कामों को लोगों के सामने लाएंगे। माता अहिल्या ने परिवार के दूर होने के बाद जिस तरह भगवान शिव की प्रतिमा को लेकर देशभर में जो काम किया, वह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। वो अपने कामों के आधार पर जीवन भर के लिए अमर हो गई। नारी सशक्तिकरण, अन्य क्षेत्र, सहित कई बड़े प्रबंधन के काम उन्हें अकेले किया। उस वक्त नदियों के किनारे महिला पुरुषों के लिए अलग घाट का निर्माण होना यह सोचना भी संभव नहीं है।सीएम यादव कार्यक्रम से रवाना होते वक्त माता अहिल्या की बड़ी प्रतिमा अपने हाथों में लेकर बाहर निकले।

कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सीएम डॉ मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि हम सब देख ही रहे हैं, जिस तेज गति से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वह क़ाबिले तारीफ है। मैं जिस साल इंदौर में शादी होकर आई उसी साल आपका (सीएम यादव) जन्म हुआ। हमारा इंदौर आगमन और आपका उज्जैन आगमन।

कार्यक्रम के बाद पालकी यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान हल्की बारिश में पालकी यात्रा में शामिल लोगों का उत्सव और बढ़ गया। यात्रा में बोहरा समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा में नेपालीजन बैंड के साथ शामिल हुए। अलग अलग वेशभूषा में महिलाएं घोड़ों पर सवार होकर निकली। यात्रा एमजी रोड, कोठारी मार्केट, एमजी रोड थाना, कृष्णपुरा छत्रियां, राजबाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। कार्यकारी अध्यक्ष अशोक डागा, सुधीर देड़गे और राम मूंदड़ा ने बताया पालकी को श्रद्धालु उठाए चलेंगे। यात्रा में इस्कॉन का रथ आकर्षण का केंद्र रहेगा।

परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुए समाजजन

नेपालीजन के साथ बोहरा समाज का बैंड नेपालीजन आकर्षण स्टेट के 14 राजाओं के प्रतीक 14 युवा तथा अहिल्या सेना की 20 युवतियों के अलावा मां अहिल्या भक्त मंडल, बंजारा समाज, दक्षिण भारतीय समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बोहरा समाज, पाउल भजन मंडली आदि के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुए।

अब नई तकनीक से इंदौर में नगर निगम भरेगा गड्ढे

इंदौर। सड़कों पर गड्ढों को लेकर इंदौरवासियों की नाराजगी झेल रहे नगर निगम ने नई तकनीक से पेचवर्क करने का फैसला लिया है। इसका ट्रायल भंडारी मिल मार्ग पर मेयर और सांसद की मौजूदगी में किया गया।

पेचवर्क वाला हिस्सा दो घंटे बाद ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया। इस पेचवर्क में पानी की तरी की जरुरत नहीं होती है। कंपनी को सड़कों के गड्ढे भरने की जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर में लगातार बारिश के कारण कई प्रमुख मार्गों पर गड्ढे हो गए। इसके कारण यातायात भी बाधित होता है। अब मौसम खुलने के बाद नगर निगम ने गड्ढे भरकर पेचवर्क करने की कवायद की है। रविवार को भंडारी मिल मार्ग पर पेचवर्क किया गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर भी मौजूद थे।

दो घंटे में हो जाएगा पेचवर्क

नई तकनीक से सीमेंट को स्पेशल केमिकल में मिलाकर गड्ढे में भरा गया। दो घंटे के बाद पेचवर्क वाला हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल लिया गया। नई तकनीक में पहले गड्ढे का उखड़ा हुआ मटेरियल बाहर निकाला जाता है, इसके बाद जो कंकड़, पत्थर को निकालकर गड्ढे को साफ किया जाता है, ताकि बेस तैयार हो जाए। फिर गड्ढे की पहली लेयर को केमिकल भरकर समतल किया जाता है। इसके लिए 25 किलो के मटेरियल में ढाई लीटर लिक्विड मिलाकर कोठी में मटेरियल तैयार किया जाता है। इसमें डामर का उपयोग नहीं होता।

खास बात यह इसमें कंपनी द्वारा बनाया गया स्पेशल इको फ्रेण्डली सीमेंट मिक्स किया जाता है। फिर इसका गड्ढे पर प्लास्टर किया जाता है। इस सीमेंट की खासियत यह है कि दो घंटे में सूख जाता है और तरी नहीं करनी पड़ती। इसके बाद सड़क का हिस्सा ट्रैफिक के लिए उपयोग किया जा सकता है।

हाई स्कूल का पहले पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए नई योजना

सुपर सेक्शन योजना से पढ़ाई पूरी कर सकेंगे 9वीं में फेल छात्र

इंदौर। हाई स्कूल के पहले कक्षा नवी में फेल होने पर पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए शासन ने एक नई योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत छात्र नेवी की परीक्षा भी दे सकता है साथ ही दसवीं की भी तैयारी कर सकता है। इस सुपर सेक्शन का नाम दिया गया है। हालांकि इस योजना के प्रति छात्रों में रुचि कम ही प्रतीत हो रही है। इसका एक कारण इसकी फीस को भी बताया जा रहा है।

जानकारी अनुसार शासन ने 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन स्कूलों का चयन किया गया, जिनमें कक्षा 9वीं में 30 या उससे ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा और उनके टीचर भी अलग से रहेंगे। यहां पर विद्यार्थी को पढ़ाकर उन्हें अगली कक्षा के लिए भी तैयार किया जाएगा ताकि वह अपनी पूरी पढ़ाई कर सके। इंदौर में करीब 3112 विद्यार्थी पिछले सत्र में फेल हुए थे। इन विद्यार्थियों के लिए कुल 31 स्कूलों का चयन किया गया। यहां पर इस तरह की पढ़ाई कराई जाएगी। वोकेशनल कोर्स भी उनके लिए जोड़ा जाएगा ताकि वह कोई रोजगार के हुनर भी सीख सके।

2400 रुपए फीस, 1400 में 10वीं का फॉर्म इस योजना को लेकर विद्यार्थी के साथ ही शिक्षक के मन में भी असमंजस की स्थिति बन गई है। सूत्रों की मानें तो करीब 2400 रुपए इन विद्यार्थियों को इस योजना में पढ़ाई के लिए देना होंगे। इसमें परीक्षा शुल्क के साथ ही पढ़ाने वाले की फीस भी शामिल रहेगी, जबकि वह मात्र 1400 रुपए खर्च करके 10वीं की परीक्षा का प्राइवेट विद्यार्थी के रूप फॉर्म भर सकता है।

गरीबी रेखा में नाम होने के बाद भी राशन नहीं लेने वालों की होगी जांच

इंदौर। *गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के बाद महीना तक मुफ्त राशन नहीं लेने वाले फर्जी गरीबों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।*

इस फर्जी गरीब जो मुफ्त का राशन नहीं ले रहे हैं जबकि अन्य सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके नाम भी गरीबी रेखा से हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये गरीब कई महीनों से राशन की दुकान पर राशन लेने भी नहीं आए हैं। ऐसे सभी राशनकार्ड धारियों के मुफ्त राशन के कार्ड अब समाप्त किए जाएंगे।

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार गरीब और अति गरीबों को हर माह प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं, चावल देती है। वहीं अंत्योदय श्रेणी के अति गरीबों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार मुफ्त देता है। खाद्य विभाग ने अब ऐसे तमाम राशन कार्डो की जांच प्रारंभ की है जो लंबे समय से मुफ्त अनाज लेने नहीं आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस समय सवा करोड़ परिवारों को मुफ्त में अनाज गेहूं चावल बांटा जा रहा है।

सुपर सेक्शन योजना से पढ़ाई पूरी कर सकेंगे 9वीं में फेल छात्र

प्रत्येक गरीब परिवार को पालता पर्ची के हिसाब से पाइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए राशन दिया जा रहा है। उन्हें उनके आधार नंबर के जरिए यह राशि मिलता है परंतु 15 से 20 प्रतिशत लोगों के बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि वे राशन लेने नहीं आ रहे हैं। अत अब खाद्य विभाग ऐसे सभी नकली गरीबों के नाम हटाने की तैयारी कर चुका है। इन लोगों को

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)